



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE Saturday, 08 Feb, 2025

Edition: International Table of Contents

Page 03 Syllabus : GS 2 : भारतीय राजनीति	निजी विधेयकों में संसद में प्रति वर्ष 100 दिन बैठने की मांग की गई है
Page 04 Syllabus : प्रारंभिक तथ्य	9 पनडुब्बियाँ, 65 जहाज़ ट्रॉपेक्स अभ्यास में भाग ले रहे हैं
Page 06 Syllabus : GS 2 : सामाजिक न्याय	मुद्रास्फीति पर विकास
Page 07 Syllabus : प्रारंभिक तथ्य	रेत में मृत समुद्री कछुओं की बाढ़
Page 08 Syllabus : प्रारंभिक तथ्य	तारों के नीचे महिलाओं की भूमिका निभाने वाले पुरुष
Page 06 : संपादकीय विश्लेषण: Syllabus : GS 2 : सामाजिक न्याय	प्रौद्योगिकी और समान शिक्षा की चुनौती



Page 03: GS 2: Indian Polity

वरिष्ठ विपक्षी सदस्य डेरेक ओ ब्रायन और मनोज कुमार झा ने प्रतिवर्ष न्यूनतम 100-120 संसदीय बैठकें अनिवार्य करने के लिए विधेयक प्रस्तावित किए हैं।

Private Bills seek sitting of Parliament for 100 days a year

The Hindu Bureau

NEW DELHI

Senior Opposition members in the Rajya Sabha Derek O'Brien and Manoj Kumar Jha have moved separate Bills seeking to make the sitting of Parliament mandatory at least for 100 days in a year. The leaders said the move is to reform the Parliamentary system by ensuring that the working hours of the House are not lost due to disruptions.

While Mr. O'Brien has proposed a minimum sitting of 100 days, Mr. Jha has sought 120 days sitting of the House annually.

Mr. O'Brien said that while the idea of a fixed calendar was explored by the General Purposes Committee of the Lok Sabha in 1955, the importance of having a minimum number of sittings was highlighted by the National Commission to Review the Working of the Constitution in 2002.

Mr. Jha said his Bill is to

provide a framework for enhancing the perforof Parliament mance through fixing a minimum number of days of sitting, introducing the provision for extending the hours of a sitting, bringing a short session in addition to the existing three sessions, instituting a mechanism to separately discuss Opposition business and compensating the hours not utilised due to disruptions.

Meanwhile, the Union Education Ministry opposed the introduction of the Coaching Institutes (Accountability and Regulation) Bill, moved by Nationalist Congress Party (Sharadchandra Pawar) MP Fauzia Khan saying that education is in the Concurrent List and the States would have to regulate the coaching centres.

But when Opposition members insisted that the Bill be introduced, the objection was withdrawn and the Bill introduced in the House.



ऐसे विधेयक की आवश्यकता

- 🔸 संसदीय बैठकों में कमी: पिछले कुछ वर्षों में संसदीय बैठकों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है।
- 1950 के दशक में, संसद की बैठकें सालाना लगभग 120-140 दिनों के लिए होती थीं, लेकिन अब यह घटकर लगभग 60-70 दिन रह गई हैं।





- 🔶 विधायी जांच सुनिश्चित करना: अधिक बैठकें विधेयकों, नीतियों और सरकारी निर्णयों की बेहतर जांच करने की अनुमति देंगी।
- लोकतंत्र को मजबूत करना: अधिक सिक्रय संसद सार्वजिनक मुद्दों का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है और जवाबदेही बढ़ाती है।
- व्यवधानों को रोकना: बार-बार व्यवधानों के कारण काम के घंटे कम हो जाते हैं; एक निश्चित कैलेंडर इष्टतम विधायी कामकाज सुनिश्चित कर सकता है।
- रिपोर्ट से सिफारिशें: संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग (2002) और पहले की संसदीय सिमितियों ने बैठकों की न्यूनतम संख्या की सिफारिश की है।

चुनौतियाँ

- 🔷 कार्यपालिका की हिचकिचाहट: सरकार प्रशासनिक बोझ और बढ़ती जांच के डर से विरोध कर सकती है।
- विपक्षी समन्वय: केवल व्यवधानों के बजाय प्रभावी बहस सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है।
- राजनीतिक सहमित का अभाव: विभिन्न राजनीतिक दलों की संसदीय बैठकों को बढ़ाने के बारे में अलग-अलग राय हो सकती है,
 जिससे इस तरह के सुधार को लागू करने में देरी हो सकती है।
- ➡ विधायी कार्यभार: यदि गहन बहस और चर्चा के बजाय विधेयकों को जल्दी से पारित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो
 अधिक बैठकें बेहतर कानून निर्माण में जरूरी नहीं हो सकती हैं।

आगे का रास्ता

- निश्चित संसदीय कैलेंडर: अनिवार्य बैठकों के साथ एक संरिवत वार्षिक कैलेंडर कार्यकुशलता में सुधार कर सकता है।
- 🔶 संसदीय समिति को मजबूत बनाना: गैर-बैठक अवधि के दौरान भी विधेयकों की विस्तृत जांच सुनिश्चित करना।
- 🟓 खोए हुए घंटों की भरपाई करना: व्यवधानों के कारण खोए हुए घंटों को वापस पाने के लिए तंत्र शुरू करना।
- बहु-सत्र मॉडल: विपक्षी व्यवसाय और नीति समीक्षा पर चर्चा करने के लिए एक छोटा सत्र जोड़ना।
- रचनात्मक भागीदारी को प्रोत्साहित करना: सांसदों के लिए प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन जैसे तंत्र शुरू करना, उत्पादक चर्चा सुनिश्चित करना और संसदीय कार्यवाही में व्यवधानों को कम करना।

UPSC Mains PYQ: 2019

प्रश्न: राष्ट्रीय विधिनिर्माता के रूप में व्यक्तिगत सांसदों की भूमिका में गिरावट आ रही है, जिसके परिणामस्वरूप बहसों की गुणवत्ता और उनके परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चर्चा करें। (250 words/15m)



Page 04: Prelims Fact

🔷 ट्रोपेक्स-25 अभ्यास में 65 जहाज, 9 पनडुब्बियाँ और 80 विमान शामिल हैं, साथ ही सेना, वायु सेना और तटरक्षक बल की संयुक्त भागीदारी भी है।

थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज (ट्रोपेक्स)

- द्विवार्षिक नौसेना अभ्यास: टोपेक्स भारतीय नौसेना का सबसे बडा द्विवार्षिक परिचालन अभ्यास है, जो हर दो साल में हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है।
- 🟓 अवधि: 2025 संस्करण (ट्रोपेक्स-25) जनवरी से मार्च तक आयोजित किया जा रहा है।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना की संचालन अवधारणा को मान्य और नवीनीकृत करना है, एक विवादित समुद्री वातावरण में पारंपरिक, विषम और संकर खतरों का जवाब देने की इसकी क्षमता का परीक्षण करना है।
- ▶ प्रतिभागी: अभ्यास में लगभग 65 भारतीय नौसेना के जहाज, 9 पनडुब्बियाँ और 80 से अधिक विमान शामिल हैं, साथ ही भारतीय सेना, वायु सेना और तटरक्षक बल की पर्याप्त भागीदारी है।
- अभ्यास चरण: इसमें बंदरगाह और समुद्री चरण शामिल हैं, जिसमें लडाकू संचालन, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, लाइव हथियार रिंग और उभयचर संचालन शामिल हैं।
- 🔸 सामरिक महत्व: यह अभ्यास संयुक्त परिचालन तत्परता को बढ़ाता है तथा भारत के समुद्री सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए समन्वित, एकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है।





Indian Navy's TROPEX

9 submarines, 65 ships taking part in TROPEX exercise

The Hindu Bureau

Indian Navy's biennial capstone Theatre Level Operational Exercise (TROPEX) is under way in the Indian Ocean Region, from January to March, in which the combined fleet, comprising approximately 65 Indian Navy ships, nine submarines, and over 80 aircraft of different types are being "put through complex maritime operational scenarios to validate tional scenarios to validate and refine the Navy's Con-cept of Operations".

This is conducted biennially with participation by all operational units of the Navy along with substantial participation of Army, Air Force, and Coast Guard assets.

'Maritime security'
"TROPEX-25 is aimed at validating Indian Navy's core warfighting skills, and ensuring a synchronised, in-tegrated response to preserve and protect national maritime security interests in a contested maritime environment against conventional, asymmetric as well as hybrid threats," the Navy said in a statement. The exercise is being

conducted in various phases – both in harbour and at sea, integrating various facets of combat operations, cyber and electronic warfare operations, live weapon firings during the joint work-up phase, and amphibious exercise.





Page 06: GS 2: Social justice: Health

 भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 6.25% कर दिया है, जो मई 2020 के बाद पहली कटौती है।

57 महीनों के बाद रेपो दर में कटौती

- इस निर्णय का उद्देश्य इस तिमाही में ब्याज दर के 4.4% और 2025-26 में औसतन 4.2%
 रहने की उम्मीदों के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- रेपो दर में कमी से घर, कार और अन्य ऋणों के लिए उधार लेने की लागत कम हो सकती
 है।

रेपो दर क्या है?

- रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है।
- यह अर्थव्यवस्था में ब्याज और तरलता को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रमुख मौद्रिक नीति उपकरण है।
- उच्च रेपो दर उधार लेना महंगा बनाती है, ब्याज को कम करती है, जबिक कम रेपो दर व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए ऋण सस्ता करके उधार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है।

मौद्रिक नीति समिति (MPC)

- मौद्रिक नीति सिमिति (एमपीसी) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का छह सदस्यीय निकाय है, जो मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है।
- इसकी स्थापना 2016 में संशोधित आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत की गई थी, और यह मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण ढांचे का पालन करती है।
- एमपीसी में छह सदस्य हैं, जिनमें गवर्नर सिहत आरबीआई के तीन सदस्य हैं, और तीन बाहरी सदस्य हैं जिन्हें सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- एमपीसी की बैठक साल में कम से कम चार बार होती है, और निर्णय बहुमत से किए जाते हैं, अगर मत बराबर होते हैं तो आरबीआई गवर्नर के पास निर्णायक मत होता है।

आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति अनुमान

आरबीआई ने 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.7% रहने का अनुमान लगाया है, जो इस वर्ष के लिए अनुमानित 6.4% से अधिक है।

Growth over inflation

The interest rate cut signals a shift in the RBI's immediate priorities

or the first time in nearly five years, the Monetary Policy Committee (MPC) of the Reserve Bank of India (RBI) pivoted on interest rates, unanimously deciding to cut the benchmark repo rate from 6.50% to 6.25%. This move, while maintaining a neutral stance, marks a significant departure from the previous bimonthly review, where the committee had opted for the status quo with a 4:2 vote. At the time, the MPC was contending with inflation at a 15-month high of 6.2% in October and a sluggish secondquarter GDP growth of 5.4%. Now, with inflation moderating to 5.2% in December, still above the RBI's 4% target, and growth projections for 2024-25 slipping to a four-year low of 6.4%, the central bank appears to be prioritising economic expansion over inflation control. RBI Governor Sanjay Malhotra, in his first policy review, highlighted the challenges posed by global economic uncertainties, including stalled disinflation, diminishing prospects of rate cuts in the U.S., and a stronger dollar pressuring emerging markets and their currencies, including the rupee. These factors have complicated policy trade-offs for India, making the case for supporting growth even stronger. The MPC justified its decision to look past current inflationary concerns, citing expectations that price pressures will ease further, with inflation projected to average 4.2% in 2025-26 from 4.8% this year. This outlook hinges on assumptions of a favourable food inflation trajectory, a normal monsoon, and a bumper harvest of key vegetables such as tomato, onion, and potato, which are, historically, major contributors to price spikes. While inflation remains a concern, the panel has signalled that weak economic growth is more pressing, especially given the second-quarter slump and limited signs of recovery since then. The RBI's post-Budget policy stance also suggests closer alignment with fiscal policy, apparently heeding the government's call for monetary and fiscal measures to work in tandem rather than at cross-purposes. Whether the Budget's stimulus measures, combined with the rate cut, will revive consumption, attract private investment, and boost growth remains uncertain.

Interestingly, had the MPC met a week later, it might have had additional justification for the rate cut, given expectations that inflation in January could have cooled to around 4.5%. With a new Governor at the helm and an upcoming appointment for the Deputy Governor overseeing monetary policy, the RBI could consider adjusting the MPC's review schedule to incorporate the latest inflation data. A slight shift in the timing of its bi-monthly meetings could make monetary policy more responsive and data-driven, enhancing the committee's ability to justify its stance with real-time economic indicators.





🔷 सामान्य मानसून को मानते हुए, मुद्रास्फीति में और गिरावट आने की उम्मीद है और धीरे-धीरे 4% लक्ष्य के साथ संरेखित होगी।

मिश्रित मांग रुझान

- ग्रामीण मांग में सुधार हो रहा है, जबिक शहरी खपत कमजोर बनी हुई है।
- 🔸 उच्च रोजगार, बजट से कर लाभ और कम मुद्रास्फीति से घरेलू खपत को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

मुद्रा और बाहरी क्षेत्र की स्थिरता

- आरबीआई किसी विशिष्ट विनिमय दर को लिक्षत नहीं करता है, लेकिन अत्यिधक बाजार अस्थिरता को कम करने के लिए हस्तक्षेप करता है।
- 🕩 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार \$630.6 बिलियन (31 जनवरी, 2025 तक) है, जो 10 महीने से अधिक के आयात को कवर करता है।
- चालू खाता घाटा एक स्थायी स्तर पर रहने की उम्मीद है।

UPSC Prelims PYQ: 2017

प्रश्न: मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है/हैं?

- 1. यह आरबीआई की बेंचमार्क ब्याज दरें तय करता है।
- 2. यह आरबीआई के गवर्नर सहित 12 सदस्यीय निकाय है और हर साल इसका पुनर्गठन किया जाता है।
- 3. यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है।
- नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) केवल 2 और 3

उत्तर: a)





Page 07 : Prelims Fact तमिलनाडु के तट पर ओलिव रिडले कछुओं की मृत्यु की संख्या में नाटकीय वृद्धि हुई है, 31 जनवरी तक 1,200 शव पाए गए।



A surge of dead sea turtles in the sand





समाचार का विश्लेषण:

- 🕩 मृत्यु दर सामान्य वार्षिक औसत से काफी अधिक है, जिससे संरक्षणवादियों और स्थानीय शेरफ़ोक के बीच चिंता बढ़ गई है।
- 🏓 विशेषज्ञ बढ़ती मृत्यु दर के लिए विनाशकारी शिंग प्रथाओं जैसे कि बॉटम ट्रॉलिंग और समुद्री नियमों के लगातार उल्लंघन को दोषी ठहराते हैं।
- अशांत मानसून धाराओं ने भी संकट में योगदान दिया है, जिससे लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए स्थिति और खराब हो गई है।





- मृत्यु दर में खतरनाक वृद्धि ने सरकार को सख्त समुद्री संरक्षण उपायों को लागू करने के लिए कार्रवाई और कानूनी जांच के लिए प्रेरित किया है।
- संरक्षणवादी और हितधारक ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने के लिए स्थायी शिंग समाधानों का आग्रह कर रहे हैं।

ऑलिव रिडले कछुआ

- ऑलिव रिडले कछुआ सबसे छोटी और सबसे प्रचुर समुद्री कछुओं की प्रजाति है, जो हिंद महासागर सिहत गर्म उष्णकिटबंधीय जल में पाई जाती है।
- यह ओडिशा के गिहरमाथा और रुशिकुल्या समुद्र तटों पर विशेष रूप से अरिबाडा नामक सामूहिक घोंसले के शिकार की घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है।
- आईयूसीएन रेड लिस्ट के तहत इसे संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची। के तहत संरक्षित किया गया है, इसके खतरों में आकस्मिक बायकैच, आवास की हानि और प्रदूषण शामिल हैं।
- 🔷 भारत समुद्री मत्स्य विनियमन अधिनियम और मौसमी शिंग प्रतिबंधों के माध्यम से कछुओं के संरक्षण को लागू करता है।
- 🔷 कछुआ बहिष्करण उपकरण (TEDs) और तटीय निगरानी जैसे संरक्षण प्रयास ओलिव रिडले संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं।





Page 08: Prelims Fact

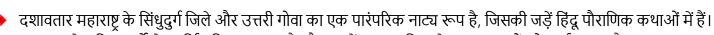
यह समाचार महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के पारंपरिक नाट्य रूप दशावतार पर प्रकाश डालता है।











यह 800 से अधिक वर्षों से प्रदर्शित किया जा रहा है और इसमें भगवान विष्णु के दस अवतारों को दर्शाया गया है।

यह प्रदर्शन धान की कटाई के बाद मई तक होता है, जो गाँव के मेलों (जात्रा) के साथ मेल खाता है।

सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण पारंपरिक रूप से केवल पुरुष ही प्रदर्शन करते हैं, यहाँ तक कि महिला भूमिकाओं में भी।





THE HINDU Daily News Analysis

- इस रूप में सुधार, संगीत और प्रतीकात्मक सहारा शामिल है। कलाकार, अक्सर किसान या छोटे व्यापारी, पूरक आय के लिए दशावतार पर निर्भर रहते हैं।
- सामाजिक मानदंडों के विकास के बावजूद, प्रदर्शनों के बारे में लैंगिक धारणाएँ महत्वपूर्ण बनी हुई हैं, जो महिला भूमिकाएँ निभाने वाले अभिनेताओं की सामाजिक स्वीकृति को प्रभावित करती हैं।







Page : 06 Editorial Analysis Technology and the challenge of equitable education

to this writer, in the open and continuing

need and the possibilities in India are

education domain for the underprivileged. The

tremendous. For example, at this time, over 40%

have completed school less than class five. Nearly

another 40% are schooled between class six and

class 10, and the remaining have completed class

children is an investment India should make to

Over the past 30 years, we have lived through

revolutions, and we are now looking at AI. With

every new wave of technology, there is new hope

and talk of revolutionising education. By the time

10. Educating mothers so that they can help

accelerate and strengthen the education of

the computer, the Internet, and mobile

mothers of schoolchildren are not schooled or

n India, the 1990s and the early 2000s were a time of education activities on a mass scale. But results from the nationwide Annual Status of Education Report (ASER) surveys of that period indicated that while enrolment and infrastructure indicators showed a rush to schools, learning indicators pointed to no change. At the same time, computers, mobile phones, and digital technology were making waves. It was a time of many possibilities and promises with digital solutions and businesses. However, it was when the COVID-19 pandemic struck that the digital revolution hit the ground in rural India. This is reflected very well in ASER data.

Smartphone use and rural households

In 2018, nearly 90% of rural households had simple mobile phones and 36% had smartphones. In 2022, the proportion of households with smartphones had risen to over 74% and, according to ASER 2024, it has grown further to 84% this year. While the percentage of children who have access to a smartphone at home is nearing saturation, the proportion of children aged between 14 and 16 years who own a smartphone has risen from 19% to about 31% within a year.

It is not clear from the ASER data whether mothers of young children have their own phones. This ownership of smartphones is important when it comes to use in supporting young children's learning and their own learning.

The main use of smartphones during the pandemic period was that of a carrier of texts, worksheets, and videos, which were a substitute for textbooks. Virtual training sessions had become common too. As the pandemic faded away, the digital skills learned during the period sustained, although some of the practices became less important and a new excitement began to build around artificial intelligence (AI).

The best promise of the digital revolution was,



<u>Madhav Chavan</u>

is a co-founder of Pratham

the technology becomes affordable, something new and exciting for the privileged shows up on the horizon, but technology has not delivered on its promise where the education of the underprivileged is concerned. One of the biggest constraints is the availability of devices.

But, as ASER 2024 data show, availability of individually owned smartphones is going to be less and less of a constraint. Most rural households already have a smartphone. Getting a second phone may be easier for many families in times to come.

No language barrier

Hardware, without a doubt, is becoming easily available. Language used to be a major impediment. It is not so any more. Writing or dictation in local languages is now possible. Translation from one language to another is easy. All the tools needed for learning are accessible, if you know what to access, where, and how. But what if there was one place in a village – let us call it school – where questions of what, where, and how were answered by an intelligent device?

Access to schools is complete. But school

attendance is still a problem. In a village or a community, some children go to a private school, some to a government school, others to private classes and some do not go to school at all. This is somewhat of a chaotic situation at the level of the village and also at the larger community level, which reflects in the quality of learning in schools.

During the pandemic, in many villages of Maharashtra, a learning programme was broadcast from a vantage point. It should be possible to work out a curriculum and broadcast schedule in villages so that group learning can be organised. Organising new schools in this manner should be possible, although, initially, there may not be many takers.

Every civilisation has created its own schooling system over the last 5,000 years. Teachers and methods in one education system did not work in another, the curriculum in one country was not a good fit in another. That was because civilisations were separated by time, space, culture, and technology. The age of empires and colonialism started integrating civilisations. Although separated by national boundaries, countries today are integrated by science and technology. Education too is an integrating factor. But so is profit. Every technological innovation, barring those promoted by philanthropists as public goods, has to look for a 'for-profit market'. Where profits cannot be made, innovations find limited use.

The prediction that hardware and devices would become inexpensive has come true but the need for a higher order and bigger hardware is growing with the innovations of AI. Will philanthropic investments be enough to help universalise the innovations that could revolutionise education? As a country, India needs to come up with a road map that allows the promise of technology to be harnessed for the benefit of those who need it the most.

road map in the field of education that allows the promise of technology to be harnessed for those who need it the most

India lacks a

GS Paper 02 : सामाजिक न्याय - शिक्षा

UPSC Mains Practice Question: : ग्रामीण भारत में शिक्षा को बढ़ाने में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करें। समान पहुँच और सीखने के परिणाम सुनिश्चित करने में क्या चुनौतियाँ बनी हुई हैं? (250 Words /15 marks)



THE HINDU Daily News Analysis

संदर्भ:

- 🟓 ग्रामीण भारत में डिजिटल तकनीक के विस्तार, खासकर कोविड-19 के बाद, ने शिक्षा की पहुँच में सुधार किया है।
- 🔷 हालाँकि, न्यायसंगत शिक्षा और प्रभावी डिजिटल एकीकरण में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में शिक्षा के रुझान

- 🟓 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में भारत में शिक्षा का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ।
- 🟓 उस समय के ASER सर्वेक्षणों की रिपोर्ट में नामांकन और बुनियादी ढाँचे के विकास में वृद्धि देखी गई।
- हालाँकि, अधिक बच्चों के स्कूल जाने के बावजूद सीखने का स्तर अपरिवर्तित रहा।
- 🔷 इस बीच, डिजिटल तकनीक, मोबाइल फोन और कंप्यूटर प्रमुखता प्राप्त कर रहे थे।

डिजिटल शिक्षा पर कोविड-19 का प्रभाव

- ग्रामीण भारत में डिजिटल क्रांति ने वास्तव में कोविड-19 महामारी के दौरान गित पकडी।
- ASER डेटा इस बदलाव को दर्शाता है, जो ग्रामीण परिवारों में स्मार्टफोन के उपयोग में वृद्धि दर्शाता है।
- महामारी से पहले, 2018 में, लगभग 36% ग्रामीण परिवारों के पास स्मार्टफोन थे।
- 🟓 २०२२ तक यह आंकड़ा ७४% और २०२४ तक ८४% तक पहुँच गया।
- 14 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों का अनुपात जिनके पास व्यक्तिगत रूप से स्मार्टफोन है, सिर्फ़ एक साल में 19% से बढ़कर 31% हो गया।

शिक्षा के लिए स्मार्टफोन का उपयोग

- महामारी के दौरान स्मार्टफ़ोन का उपयोग मुख्य रूप से वर्कशीट, वीडियो और ऑनलाइन कक्षाओं तक पहुँचने के लिए किया गया था।
- 🟓 छात्रों और शिक्षकों के लिए वर्चुअल प्रशिक्षण सत्र आम हो गए।
- महामारी के बाद भी, उस दौरान सीखे गए डिजिटल कौशल उपयोगी बने रहे।
- हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि छोटे बच्चों की माताओं के पास स्मार्टफोन है या नहीं, जो बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत में डिजिटल शिक्षा के अवसर

- 🏓 वंचित समुदायों के लिए खुली और सतत शिक्षा में एक महत्वपूर्ण अवसर निहित है।
- स्कूली बच्चों की कई माताओं की औपचारिक शिक्षा बहुत कम है:
- 40% से ज़्यादा बच्चों ने या तो कोई स्कूली शिक्षा नहीं ली है या कक्षा 5 से कम पढ़ाई की है।
- अन्य 40% ने कक्षा 6 और कक्षा 10 के बीच की पढ़ाई पूरी की है।
- 🟓 शेष ने कक्षा 10 पास की है।





➡ माताओं को शिक्षित करने से उनके बच्चों की शिक्षा में सहायता करने की उनकी क्षमता बढ़ेगी, जिससे यह एक मूल्यवान निवेश बन जाएगा।

वंचित वर्ग के लिए डिजिटल शिक्षा में चुनौतियाँ

- 🟓 कई तकनीकी प्रगति के बावजूद, वंचित वर्ग के लिए शिक्षा में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है।
- 🟓 व्यक्तिगत उपकरणों की उपलब्धता एक बड़ी बाधा रही है।
- 🔸 हालांकि, ASER 2024 के डेटा से पता चलता है कि स्मार्टफ़ोन का स्वामित्व बढ़ रहा है, जिससे यह सीमा कम हो रही है।
- अधिक परिवारों को निकट भिवष्य में दूसरा फ़ोन खरीदना आसान लग सकता है।

शिक्षा में भाषा संबंधी बाधाओं को तोड़ना

- 🟓 हार्डवेयर अधिक सुलभ हो गया है, और भाषा संबंधी बाधाएँ कम हो रही हैं।
- 🟓 स्थानीय भाषा में श्रुतलेख और अनुवाद उपकरण अब सीखना आसान बनाते हैं।
- छात्रों को यह मार्गदर्शन देने में चुनौती बनी हुई है कि उन्हें सीखने के संसाधनों तक क्या, कहाँ और कैसे पहुँचना है।

स्कूल में उपस्थिति और सीखने की गुणवत्ता से जुड़े मुद्दे

- जबिक ज्यादातर बच्चों की स्कूलों तक पहुँच है, लेकिन उपस्थिति में कोई अंतर नहीं है।
- गाँवों में निजी स्कूलों, सरकारी स्कूलों या निजी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों का मिश्रण है, जबिक कुछ बच्चे स्कूल ही नहीं जाते।
- 🔸 इसका नतीजा असमान सीखने के नतीजों में होता है।
- महामारी के दौरान, महाराष्ट्र के गाँवों ने छात्रों को सीखने के कार्यक्रम प्रसारित किए।
- 🟓 ग्रामीण समुदायों में समूह सीखने को व्यवस्थित करने के लिए एक समान मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकता है।

शिक्षा प्रणालियों का विकास

- 🔷 ऐतिहासिक रूप से, प्रत्येक सभ्यता ने अपनी शिक्षा प्रणाली विकसित की।
- 🟓 उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण ने इन प्रणालियों को एकीकृत किया।
- 🔷 आज, प्रौद्योगिकी और विज्ञान देशों में शिक्षा प्रणालियों को और जोड़ते हैं।
- हालाँकि, तकनीकी प्रगति अक्सर लाभ के लिए प्रेरित होती है, जो वंचित समूहों तक उनकी उपलब्धता को सीमित करती है।

निष्कर्ष

- हालाँकि हार्डवेयर सस्ता हो गया है, लेकिन AI और नई तकनीकों के लिए उच्च-क्रम वाले उपकरणों की आवश्यकता होती है।
- 🕩 परोपकारी निवेश शैक्षिक प्रौद्योगिकी तक पहुँच बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।



 भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए एक सुनियोजित रणनीति की आवश्यकता है कि प्रौद्योगिकी उन लोगों को लाभ पहुँचाए जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

